

to price pressures. As a general measure to control credit, the Bank rate was raised in January, 1971 from 5 to 6 per cent and the cost of Reserve Bank refinance to commercial banks was stepped up.

In the case of commodities in short supply, e.g., raw cotton, edible oils and steel, Government has been arranging imports to augment supplies. In the case of a number of industrial goods, recourse is taken to price and distribution controls in order to hold the price line. The Government also regulates forward transactions and there is a ban on forward trading in foodgrains and major oilseeds.

The Government has built up a sizeable buffer stock of foodgrains—physical stocks with Central and State Governments amounted to 5.8 million tonnes at the end of February, 1971—and is maintaining an efficient system of public distribution. A constant watch on the availability and price trends of essential commodities, such as foodgrains, edible oils, textiles, drugs etc. is kept by the Organisation of Commissioner of Civil supplies.

मध्यप्रदेश में अफीम की खेती करने वाले किसान

172. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या

बित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम जिलों में अफीम की खेती करने वालों की संख्या क्या थी ;

(ख) उक्त अवधि में उपर्युक्त दो जिलों में अफीम की प्रति एकड़ औसत उपज कितनी थी ;

(ग) सरकार द्वारा उक्त जिलों में अफीम की वसूली के समय वसूली केन्द्र खोलने संबंधी नियम अथवा कमीटी क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अफीम की खेती से संबंधित नियमों में संशोधन करन का है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

बित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :—

अफीम वर्ष	जिले का नाम	अफीम के काश्तकारों की संख्या	70 डिग्री घनत्व पर प्रति एकड़ औसत उपज
1969-70	मंदसौर	56,612	12.29 किलोग्राम
1969-70	रतलाम	11,460	11.13 किलोग्राम

(ग) प्राप्ति—केन्द्र नियत करने के मुख्य सिद्धान्त ये हैं :—

- पोस्ट उगाने वाले गावों की समीपता ;
- आवास तथा जल की सुविधा ;
- नकदी तथा अफीम को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था ।

इस सम्बन्ध में तहसील/परगने के मुख्य

कार्यालयों अथवा बड़े गावों को तरजीह दी जाती है जहां सामान्यतः तैल करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

खालियर नगर का दर्जा बढ़ाया जाना

173. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या

बित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खालियर को 'बी' श्रेणी का